(ग) इन केन्द्रों के चलाने में कितना धन व्यय हुआ है और उनसे कितनी आय हुई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या** LT-4662/65]

(ग) 1964–65 में रेलों द्वारा किया गया खर्च लगभग 1.6 लाख रुपये ।

1964–65 में हस्तकला केन्द्रों में रेल कर्मचारियों के परिवारों द्वारा कपड़े आदि की सिलाई से हुई आमदनी : लगभग 7.6 लाख रुपये ।

कच्चे लोह, तांबे, जिंक का उत्पादन

927. **डा० महादेव प्रसाद** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कच्चे लोहे, तांबे और जिंक की भट्टियों (फर्नेस) की स्थापना के लिये पोलैंड ने भारत को सहायता देने के लिये कहा था ; और

(ख) यदि हां, तो सहायता की शर्तें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री सजीव रेड्डी) : (क) और (ख). पोलैण्ड ने कच्चे लोहे के उत्पादन के लिए धमन भट्टियां लगाने में अभिरुचि दिखाई है । इस प्रस्ताव पर कच्चे लोहे के लिए धमन भट्टियों के शाक्यता प्रतिवेदनों की जांच के पश्चात् विचार किया जाएगा । ये प्रतिवेदन प्राप्त किये जा चुके हैं । विचार करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन धमन भट्टियों का निर्माण करने की स्थिति में हैं ।

पोलैण्ड की सहायता से अग्निगुंडाला ताम्र-प्राप्रव्य-स्थल (आन्ध्र प्रदेश) का विकास करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

पोलैण्ड द्वारा दिए गए ऋण से विशाखापत्तनम में जस्ते की एक भट्टी स्थापित की जाएगी जिसकी वार्षिक क्षमता 30,000 टन धातु की होगी । इसमें आयात किया गया जस्ते का चूरा इस्तेमाल किया जाएगा । विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए मैसर्स सेंट्रोजेप के साथ किए जाने वाले करार का निरीक्षण किया जा रहा है और यह आशा है कि इसे शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जाएगा ।

जस्त-भट्टी के लिए रुपया पोलैण्ड के साथ हुए ऋण समझौते से लगाया जाएगा जिस पर दोनों सरकारों ने 16-11-1962 को हस्ताक्षर किए थे और जिसके अन्तर्गत पोलैण्ड भारत को 15.5 करोड़ रुपए का ऋण देगा । करार की मोटी-मोटी शर्तें निम्नलिखित हैं :—

(क) ऋण पर ब्याज की दर ढ़ाई प्रतिशत प्रति वर्ष होगी । देय ब्याज का हिसाब हर साल 30 जून और 31 दिसम्बर को लगाया जाएगा ।

(ख) मूलधन 8 समान वार्षिक किस्तों में वापिस किया जाएगा । पहली किस्त इस प्रायोजना के परिचालन के लिए अन्त में भेजी गई मशीनों और साज सामान के बीजक अथवा अन्य अभिसंविदित दस्तावेज की तारीख से एक वर्ष पश्चात् देय होगी ।

(ग) मूलधन और ब्याज की अदायगी की रकमें भारत-पोलैण्ड ऋण खाते में जमा होगी और इस प्रकार जमा हुई रकम पोलैण्ड को निर्यात करने के लिए भारतीय माल खरीदने के लिए खर्च की जाएगी ।

Development of Sericulture

928. **Shri Linga Reddy:** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the amount spent on the various

schemes for the development of sericulture in the State of Jammu and Kashmir during the year 1964-65;

(b) the reasons for the slow progress made in the implementation of the schemes; and

(c) the action taken by the Central Silk Board in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri S. V. Ramaswamy): (a) Rs. 11.23 lakhs as against an allocation of Rs. 20.13 lakhs.

(b) The reasons for slow progress in the implementation of the schemes are as under:—

- (i) Delays in the acquisition of land;
- (ii) Delay in the construction of buildings by the State Public Works Department;
- (iii) Administrative delays in sanctioning the schemes by the Government of Jammu and Kashmir; and
- (iv) Adverse weather conditions during the year.

(c) The Central Silk Board took the following action:—

(i) The Chairman and the Vice-Chairman of the Board wrote to the State Minister of Sericulture drawing his attention to the slow progress in the implementation of the schemes.

(ii) The Vice-Chairman of the Board convened a special meeting of the Members of Parliament from Jammu & Kashmir on 28-3-1965 and brought to their notice the poor performance of the State in the utilisation of funds for the development of Sericulture Industry.

(iii) The Board has recently set up a Liaison Office at Srinagar with a view to maintaining close contacts with the State Authorities for speedy implementation of the Sericultural Schemes.

(iv) The technical officers of the Board also periodically visit the State in order to watch the progress.

Chik-Ballapur-Kolar-Bangalore Railway Line

929. **Shri Linga Reddy:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) when the Chik-Ballapur-Kolar-Bangalore narrow gauge railway line was laid;

(b) whether there is a proposal to replace the same by a broad gauge railway line; and

(c) if so, when and estimated outlay involved?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath): (a) Bangarpet-Kolar-Chik-Ballapur section was opened to traffic in stages in the years 1913—1916. The Chik-Ballapur-Bangalore section was opened to traffic in stages in the years 1915—18.

(b) No.

(c) Does not arise.

Tin Plates

930. **Shri R. Barua:** Will the Minister of **Industry and Supply** be pleased to state:

(a) the present requirements of tin plates for containers in India;

(b) whether it can be met from the local production;

(c) if not, the other sources of supply; and

(d) whether Government anticipate rise in the price of tinned food due to the inadequate supply of tin plates?

The Deputy Minister in the Ministry of Industry and Supply (Shri Bibudhendra Misra): (a) to (d). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Truck-Train Collision at Jehanabad

931. **Shri A. P. Sharma:**
Shri P. C. Borooah:
Shri P. R. Chakraverti:
Shri Bagri:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a